

पूरा गन्ना मूल्य चुकाने वाली मिलों को मिली मदद

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

पिछले पेरई सत्र में घोषित 280 रूपए प्रति कुन्तल के गन्ना मूल्य का शतप्रतिशत भुगतान करने वाली प्रदेश की ग्यारह चीनी मिलों को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में कुल 3196.368 लाख रूपए की राशि अनुमोदित कर दी है।

प्रदेश सरकार ने मिलों को 20 रूपए प्रति कुन्तल के बजाए 17 रूपए 03 पैसे प्रति कुन्तल की ही प्रतिपूर्ति की सुविधा दी थी। इसमें से अब छह रूपए प्रति कुन्तल की वित्तीय मदद जारी की गई है। मगर यह छह रूपए प्रति कुन्तल की मदद सिर्फ उन्हीं निजी मिलों को मिलेगी तो 30 सितम्बर तक पिछले गन्ना बकाए का शतप्रतिशत भुगतान कर देंगी।

प्रमुख सचिव राहुल भटनागर ने शुक्रवार को कहा कि इन 11 मिलों में मोहिउद्दीनपुर, रोहानाकलां, सकौती, खड्डा, बिसवां, परसेण्डी, पीलीभीत, बुलंदशहर, मोतीनगर, टोडरपुर व टिकौला की शुगर मिल्स लि. टिकौला शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि वित्तीय मदद के लिए प्रदेश सरकार की शर्त को अभी तक



सिर्फ ग्यारह मिलें ही पूरा कर पाई हैं। छह अन्य मिलों ने अपने दावे पेश किए हैं मगर बाकी बची 79 निजी मिलों प्रदेश सरकार की यह वित्तीय मदद नहीं मिल पाएगी। निजी क्षेत्र की शेष चीनी मिलों द्वारा शतप्रतिशत भुगतान करवाए जाने की कोशिश जारी है। उन्होंने बताया कि 27 निजी चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका भुगतान 85 फीसदी से अधिक हो चुका है। इन चीनी मिलों द्वारा बाकी बचे गन्ना मूल्य का भुगतान भी जल्द किए जाने की उम्मीद है।

गन्ना मूल्य तय करने की कमेटी बनी:
प्रदेश की अखिलेश सरकार ने अगले पेरई सत्र के लिए गन्ना मूल्य निर्धारण के बाबत राज्य स्तरीय कमेटी गठित कर दी है।

HINDUSTAN

20/09/2014 Pg 10